there is also a move towards strengthening of our cultural relations with the ASEAN countries, because we have profound cultural relations based on Buddhism, Hinduism and other cultural artefacts. Are you moving on that also or simply confining yourselves to terrorism and economics?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय ने जो सवाल पूछा है वह बिल्कुल सही पूछा है जो हमारा ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट का जो प्रमुख भाग है, वह भारत और आसियान देशों का जो सांस्कृतिक पहलू है, उसमें उसके महत्व को स्वीकार किया है और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे सांस्कृतिक संबंध और बेहतर होंगे।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I see that there is now a great enthusiasm and commitment of our Government towards the ASEAN summit. At the same time we see that we are not keen about the SAARC summit. Is it our policy now to look at larger regional groupings at the cost of SAARC? If not. what is the role of the SAARC? I am putting this question keeping in view the fact that our own Foreign Minister had fixed the date in Kathmandu for its meeting in January. Again, we repeated this commitment in NewYork in September. I would like to know from the hon. Minister whether we are withdrawing from the SAARC. Does it not mean dilution of our Interest in the SAARC?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, हालांकि इस सवाल का इससे संबंध नही है लेकिन फ़िर भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि सॉर्क को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है। सॉर्क की सफ़लता कुछ शर्तो पर निर्भर करती है। जब तक दूसरे देश उसमें अपना समर्थन नही देंगे तब तक उसकी सफ़लता हम अकेले पूरा नही कर सकते है। जहां तक आसियान से बढ़ते हुए हमारे संबंधों का सवाल है वह माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, हम आसियान से अपना संबंध बढ़ाना चाहते है और आने वाले दिनों में व्यापार, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तौर पर यह बेहतर होगा।

Provision of plots/flats to EPF lVlembers

*331. SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Govemment have since decided to provide plots and flats at low cost to all 3.5 crore members of the Employees Provident Fund;

(b) whether Employees Provident Fund members would not incur any expense;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the proposed scheme would cover the metropolitan cities too;

(e) if so, the names of such cities; and

(f) by when the scheme is likely to be launched?

THE MINISTER OF LABOUR {SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (f) The Central Board of Trustees {Employees Provident Fund) which is a tripartite body, at its 158th meeting held on 22.10.2002 has, in principle, approved launching of a housing scheme for Employees Provident Fund subscribers. A letter has been written to Chief Ministers of all the States for providing the houses/plots at cheaper rates; the cost of which shall be borne by the members. It Is proposed to implement the scheme at an early date. The scheme is proposed to cover the EPF subscribers all over the country.

श्री नाना देशमुख : सभापति जी, मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि साढ़े तीन करोड़ कर्मचारी जो प्रॉविडेंट फ़ंड देते है, उनके लिए सस्ते दामों पर भूखंड और फ़्लैट्स देने की योजना है, तो क्या ये भूखंड तथा फ़्लैट्स जो दिए जायेंगे उसमें कर्मचारियों को अपने प्रॉविडेंट फ़ंड से भी कुछ पैसा देना पड़ेगा ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय सभापति जी, मैं ने इस बारे में उत्तर में बताया हैं कि उनके जितने भी कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य है, जब उन को मकान बनाने की आवश्यकता पड़ती थी तो 36 महीने की तनख्वाह के बराबर ही उनको उस में से पैसा निकालने दिया जाता था और अनुभव से पता चला कि वे कर्मचारी उस पैसे में मकान नही बना पाते थे । उस पैसे को वे मकान बनाने के नाम से लेते थे, लेकिन वह पैसा इधर-उधर खर्च हो जाता था क्योंकि इतने थोड़े पैसे में मकान बन नही पाते थे । वे बिना मकान के रह जाते थे और पैसा भी उन का निकल जाता था । महोदय, लगभग 50 दिन पहले, 22 अक्टूबर की सेंट्रल बोर्ड ऑफट्रस्टीज की मीटिंग में यह तय किया गया कि उन के लिए मकान बनाने की कोई योजना बनायी जानी चाहिए क्योंकि इस तरह से तो जिंदगी में कभी उन को मकान नही मिल पाएगा । सभापति महोदय, सोशल सेक्युरिटी के लिए प्रमुख तीन चीज़े होती है ।

श्री सभापति : आप ने यह तय कर दिया, आगे वह पूछ लेंगे ।

श्री साहिब सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं वही बता रहा हूं कि सोशल सेक्युरिटी में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको मकान मिले । इस के लिए हम ने राज्य सरकारों से चर्चा की, दिल्ली में मकान देने के लिए डी0डी0ए0 और अर्बन डवलपमेंट मिनिस्टर से चर्चा की और यह तय किया कि उन लोगों का जितना पैसा जमा है, वह पैसा उसमें से देंगे और बाकी कमी रहेगी तो सस्ती दरों पर लोन दिलवाएंगे । हम ने राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की है कि वह उन्हें सस्ते दामों पर ज़मीन दिलवाए, मकान बने-बनाए हों तो वे उन्हें सस्ते दामों पर मिलें ताकि उन्हें भी मकान उपलब्ध हो सकें ।

श्री नाना देशमुख : सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अहमदाबाद में अपनी प्रेस कांफ़रेंस में कहा था कि हम एक लाख करोड़ रूपया, साढ़े चार लाख कर्मचारियों के आवासों के लिए उन्हें देने जा रहे है जिस के लिए उन्हें कुछ भी नही देना पड़ेगा । क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध है ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय सभापति जी, मैंने यह कहा है कि हमारे पास कर्मचारियों का करीब एक लाख 25 हजार करोड़ रूपया जमा है । उस पैसे से जहां हम मकान बनाएंगे, उसके लिए उसमें से खर्च करेंगे । उसके लिए हमें अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता नही पड़ेगी । जो कर्मचारी मकान लेना चाहेंगे, उनका अपना कंट्रीब्यूशन उसमे से चला जाएगा और उनको जो जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जो दूसरी लोनिंग एजेसीज है जैसे कि हुड़को है, उसके माध्यम से हम उनको लोन सस्ते दरों पर दिलवाएंगे । उसके बाद उनका रिपेमेंट का जो सिस्टम है, उसके अनुसार वह पैसा इंस्टालमेंटस में वापिस चला जाएगा । इस तरह वह कर्मचारियों का या दूसरी लोनिंग एजेंसीज का पैसा होगा । इसमें फ़र्क यह होगा कि चूंकि वे मकान नही बना पाते थे । अब उनको रहने के लिए मकान बनाने के लिए सस्ते दर्रो पर पैसा मिल सकेगा ।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि से जो मकान बनाने जा रहे है, आपकी यह योजना कितने वर्षो में पूरी होगी और उसके साथ ही आप कर्मचारी की प्रोवीडेंट फ़ंड राशि का उपयोग करेंगे, लेकिन सरकार का उसमें कितना योगदान होगा ? क्योंकि जब उसके प्रोवीडेंट फ़ंड की सारी राशि उसमें लग जाएगी तो भविष्य में अपना परिवार चलाने के लिए पैसा कहां से लाएगा ? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय सभापति जी,माननीय सदस्य ने दो अहम सवाल पूछे है । एक

तो यह कि इस योजना में कितना समय लगेगा । महोदय, हम ने सभी राज्यों के हमारे प्रोवीडेट फ़ंड कमिश्नर्स से कहा हैं कि आप इसके लिए इंडस्ट्रीज से बात करें । महोदय, पूरे देश में करीब साढ़े 3 लाख ऐसे एस्टब्लिशमेंट हम से कवर्ड है जिनकी पहचान उन्होंने की है । उन सब से पूछा है कि कौन-कौन से आपके कर्मचारी मकान लेना चाहते हैं ? एक तरफ़ तो हमने यह प्रक्रिया शुरू की है और उनके हमारे पास नम्बर आने शुरू हो गए है, दूसरी तरफ़ राज्य सरकार के सभी मुख्य मंत्रियों से हमने प्रार्थना की है कि आपके फ़्लां-फ़्लां शहर के अंदर हमारे इतने पी0एफ़0 के इम्पलाइज़ है और उनमें से कम से कम अंदाजन लगभग 25 परसैंट मकान लेना चाहेंगे, आप उनको कहां-कहां ज़मीन दे सकते है क्योंकि ऐक्विजीशन कॉस्ट पर आपको ज़मीन देनी है, उसकी व्यवस्था आप करें । ज्यों ही उस प्रदेश या शहर में रहने वाले लोगो के बारे में हमें पता चलेगा कि कितने लोग मकान लेना चाहते है और ज्यों ही हमें ज़मीन मिलेगी, हम उस पर काम करना प्रारम्भ कर देंगे । तो हम तो जल्दी से जल्दी बनाना चाहते है, लेकिन यह डिपेंड करता है ...

श्री सभापति : इनका प्रश्न दूसरा है ।

श्री साहिब सिंह वर्मा : यह भी प्रश्न था इनका कि कब तक बनाएंगे ।

श्री सभापति : इनका प्रश्न है कि केन्द्र सरकार का योगदान कितना है ।

श्री साहिब सिंह वर्मा : इनका यह भी प्रश्न था कि कब तक आप बनाएंगे, यह प्रश्न का पहला भाग था ।

श्री सभापति : वह छोड़ दीजिए, आप तो यह बताइए कि सरकार कितना योगदान दे रही है ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : प्रश्न का पहला भाग, जो इन्होंने पूछा कि सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है ? मैं समझता हूं कि सरकार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि ऐज़ इट इज़ जैसे डी0डी0ए0 से हमने तय किया कि उनकी ज़मीन की कीमत और उनकी मकान की कीमत, जितनी एक आदमी को ...

श्री सभापति : आप सीधा यह बताइए कि पी0एफ़0 की राशि के अतिरिक्त क्या सरकार कोई आर्थिक रूप से सहायता भी करेगी ?

श्री साहिब सिंह वर्मा : आर्थिक रूप से सरकार इसी मायने में सहायता कर रही है कि वह सस्ते दामों पर ज़मीन दिलवाएगी, सस्ते दामों पर मकान दोलवाएगी, सही रेट पर दिलवाएगी । नकद पैसा केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से उसमें देने की कोई योजना नही है ।